



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 2004/वैशाख 24, 1926

No. 441]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 2004/VAISAKHA 24, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2004

का.आ. 573(अ).— लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् लिट्टे कहा गया है) एक ऐसा संगम है, जिसका आधार वस्तुतः श्रीलंका में है किंतु जिससे सहानुभूति रखने वाले, जिसके समर्थक और एजेंट भारत की भूमि पर हैं ;

और लिट्टे का सभी तमिलों के लिए पृथक् स्वदेश (तमिल ईलम) प्राप्ति के उद्देश्य से भारत की संप्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता को खतरा है और संघ से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का सत्तांतरण और संबंध-विच्छेद करता है, इस प्रकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिधि के भीतर आता है ;

और लिट्टे के लिए समर्थन देने के लिए लिट्टे समर्थक शक्तियों द्वारा श्रीलंका में उत्पात किया जा रहा है और प्रतिबंध के होते हुए भी इसके कारण जुलूस, धरने आदि हो रहे हैं जिसके कारण तमिलनाडु राज्य में अशांति है और उसकी सुरक्षा खतरे में हैं ;

और अधिकांश आपराधिक मामलों की, जिनमें लिट्टे और तमिल नेशनल रिद्राइबल फ्रन्स (टी.एन.आर.टी.) तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.) और तमिलियर पासराई जैसे लिट्टे समर्थक ग्रुप अंतर्बलित हैं, दोषसिद्धि में समाप्ति हुई है किंतु तमिल ईलम धारणा अभी तक तमिलनाडु में लिट्टे समर्थक समूहों के बीच जो उस भेद्य स्थिति में योगदान कर रही हैं, जिसमें लिट्टे का भारत में विधिपूर्ण संगम के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करना, यदि अनुज्ञात कर दिया जाए तो, भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अत्यधिक अहितकर होगा ;

और लिट्टे श्री लंका में अत्यधिक सशक्त, अत्यधिक घातक और सुसंगठित आतंकवादी बल बना हुआ है और उसके तमिलनाडु राज्य और दक्षिण भारत के कतिपय हिस्सों में गहरे संपर्क हैं । लिट्टे तमिलनाडु राज्य का उपयोग श्रीलंका को दवाओं के अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल जैसे आवश्यक मदों की तस्करी के लिए आधार के रूप में कर रहा है ।

और जब तक श्री लंका, तमिल ईलम के लिए मांग से, जो श्री लंका तमिलों और श्री लंका में भारतीय तमिलों के बीच भाषात्मक, सांस्कृतिक, जातीय, ऐतिहासिक लगाव के कारण तमिलनाडु में जोरदार गूंज पाती है, विभाजित जातीय संघर्ष की स्थिति में रहता है, तब तक लिट्टे कठोर आतंकवादी आंदोलन बना रहेगा तथा तमिलनाडु में लिट्टे का समर्थक आधार बढ़ाने के लिए विलगाव संबंधी भावना को उत्तेजित करने का प्रयास करेगा ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से लिट्टे एक विधि विरुद्ध संगम है और सभी संभव साधनों द्वारा सभी ऐसे मृथकवादी क्रियाकलापों का नियंत्रण करने के लिए लगातार बहुत अधिक आवश्यकता है ;

और केन्द्रीय सरकार के पास जानकारी है कि —

- (i) लिट्टे काडर / अलग हुए दलों जिनकी पहचान हाल में ही तमिलनाडु राज्य में हुई है, से संकेत मिलता है कि तमिलनाडु में भेजे गए काडरों का लिट्टे द्वारा अविधिमान्य क्रियाकलापों के लिए उपयोग किया जाएगा ;
- (ii) पाबंदी के होते हुए भी, लिट्टे समर्थक संगठनों और व्यक्तियों के क्रियाकलापों के बारे में भारत में सूचना मिली है और इन बलों द्वारा लिट्टे को उनका समर्थन बढ़ाने का प्रयास किया गया है ;
- (iii) लिट्टे के नेता अपने संगठन द्वारा भारत की नीति के प्रति द्वेष रखते हैं और प्रतिक्रिया में राज्य मशीनरी द्वारा उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखा जा रहा है । तमिलनाडु राज्य विधान सभा में लिट्टे नेता वी०प्रभाकरन के प्रत्यर्पण का संकल्प पारित करने पर भारत और श्रीलंका में लिट्टे समर्थक तत्वों द्वारा तीव्र अलोचना की गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लिट्टे के पूर्वोक्त क्रियाकलाप भारत की संप्रभुता और राज्य क्षेत्रीय एकता तथा लोक व्यवस्था के लिए खतरा बनाए हुए हैं और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं और इसलिए उसे विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार की आगे राय है कि (i) क्योंकि भारत की अखंडता और संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सतत हिंसक और विभाजक क्रियाकलापों के कारण ; और (ii) क्योंकि यह लगातार भारत विरोधी मनःस्थिति अपनाए हुए है और इससे भारतीय राष्ट्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा बने रहने के कारण यह आवश्यक है कि लिट्टे को तुरंत प्रभाव से “विधि विरुद्ध संगम” घोषित किया जाए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम ; 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिबरेशन टाइगर्स आफ तमिल ईलम (लिट्टे) को ‘विधि विरुद्ध संगम’ घोषित करती है और यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जाए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही तुरंत प्रभावी होगी ।

[फा. सं. I-11034/9/2003-आई.एस.(III)]

राकेश, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2004

**S.O. 573(E).—** WHEREAS the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association actually based in Sri Lanka but having sympathizers, supporters and agents on the Indian soil ;

AND WHEREAS the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of an unlawful activity ;

AND WHEREAS, the turbulence in Sri Lanka is being exploited by pro-LTTE forces to draw up support for the LTTE and its cause by taking out processions, demonstrations, etc., in spite of the ban, causing disquiet and threat to the security of the State of Tamil Nadu;

AND WHEREAS most of the criminal cases involving the LTTE and pro-LTTE groups like Tamil National Retrieval Troops (TNRT), Tamil Nadu Liberation Army (TNLA) and Tamiliar Pasarai, have ended in conviction but the Tamil Eelam concept still remains as a goal among the pro-LTTE groups in Tamil Nadu. The forces are still at work to further its cause thereby contributing to the vulnerable milieu in which the LTTE's free functioning in India as a lawful association, if allowed, would be highly detrimental to the sovereignty and territorial integrity of India;

AND WHEREAS the LTTE continues to be an extremely potent, most lethal and well-organized terrorist force in Sri Lanka and has strong connections in Tamil Nadu and certain pockets of southern India. The LTTE continues to use the State of Tamil Nadu as the base for carrying out smuggling of essential items like petrol and diesel, besides drugs to Sri Lanka;

AND WHEREAS the LTTE will continue to remain a strong terrorist movement and stimulate the secessionist sentiments to enhance the support base of the LTTE in Tamil Nadu as long as Sri Lanka continues to remain in a state of ethnic strife torn by the demand for Tamil Eelam which finds a strong echo in Tamil Nadu due to the linguistic, cultural, ethnic and historical affinity between the Sri Lankan Tamils and the Indian Tamils in Sri Lanka.

AND WHEREAS for the reasons aforesaid, the Central Government is of the opinion that the LTTE is an unlawful association and there is a continuing strong need to control all such separatist activities by all possible means;

AND WHEREAS the Central Government has the information that –

- (i) enquiries on the activities of the LTTE cadres/dropouts who have been traced out recently in the State of Tamil Nadu would suggest that the cadres sent to Tamil Nadu would ultimately be utilized by the LTTE for unlawful activities;

- (ii) the activities of pro-LTTE organizations and individuals have come to notice in India, despite the ban in force and attempts have been made by these forces to extend their support to the LTTE;
- (iii) the LTTE leaders have been cynical of India's policy on their organization and reaction of the State machinery in curbing their activities. The resolution passed in the Tamil Nadu State Assembly to extradite the LTTE leader V. Prabhakaran, evoked strong criticism from pro-LTTE elements in India and in Sri Lanka;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose threat to, and are detrimental to, the sovereignty and territorial integrity of India as also public order and, therefore, should be declared as an unlawful association;

AND WHEREAS the Central Government is further of the opinion that because (i) of its continued violent and disruptive activities prejudicial to the integrity and sovereignty of India; (ii) it continues to adopt a strong anti-India posture and also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare the LTTE as "an Unlawful association" with immediate effect;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and proviso to sub section (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. I-11034/9/2003-I.S. (III)]

RAKESH, Jt. Secy.